

अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत

अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत

भारत की अंतरिक्ष यात्रा - शुरुआत

- 1962- डॉ. विक्रम साराभाई द्वारा INCOSPAR की स्थापना
- 1963- अमेरिका द्वारा आपूर्ति किये गए रॉकेट नाइक-अपार्चों को शुम्बा (केरल) से लॉन्च किया गया

शुरुआती दिनों में

- 1969 - INCOSPAR, इसरो (ISRO) में परिवर्तित हुआ
- 1975 -
 - भारत का पहला उपग्रह- आर्यभट्ट लॉन्च किया गया
 - सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट (SITE) लॉन्च किया गया
 - भारत की पहली बड़ी परियोजना; प्रौद्योगिकी को एक शैक्षिक उपकरण के रूप में उपयोग करने का प्रयास किया
- 1980 - INSAT सीरीज और SLV-3 को लॉन्च किया गया
- 1994 - PSLV को लॉन्च किया गया
- 2001 - GSAT-1 (GSAT श्रृंखला का पहला) लॉन्च किया गया

मिशन शक्ति (2019) - सैन्य और सामरिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उपग्रहों को नष्ट करने हेतु DRDO और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक एंटी-सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण

SSLV-D2 इसरो का सबसे छोटा लॉन्च व्हीकल है जिसे हाल ही में वर्ष 2023 में लॉन्च किया गया था

भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था

- 2020 में ~9.6 बिलियन डॉलर; 2025 तक 13 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है
- शेयर - सरकार (~20%), मीडिया और मनोरंजन (26%), उपभोक्ता और खुदरा सेवाएँ (21%)

पहला अंतरिक्ष युग

- यह 1951 में उपग्रह स्तुतनिक 1 (USSR द्वारा) के प्रक्षेपण के साथ शुरू हुआ
- 1961 में, यूरी गगारिन अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने

दूसरा अंतरिक्ष युग

- वर्तमान समय में जहाँ अधिकांश खिलाड़ी निजी कंपनियाँ हैं
- 2020 के बाद से वैश्विक अंतरिक्ष लॉन्चिंग का 90% कार्य निजी क्षेत्र द्वारा किया गया है
- वर्ष 2022 में 180 रॉकेट लॉन्च हुए; उनमें से 61 स्पेसएक्स द्वारा किये गए
- स्टारलैंक वर्तमान में 3,500 से अधिक उपग्रहों के समूह का संचालन करता है

भारत और विश्व अंतरिक्ष डोमेन

- वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में छठा सबसे बड़ा खिलाड़ी; विश्व की की स्पेस-टेक कंपनियों का ~3.6% (2021 तक)

- इसमें अग्रणी स्थान अमेरिका का है (अंतरिक्ष-तकनीक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी कंपनियों का 56.4%)

- अन्य शीर्ष 5 खिलाड़ी - यूके (6.5%), कनाडा (5.3%), चीन (4.7%) और जर्मनी (4.1%)

भारतीय निजी कंपनियाँ

- वर्तमान में अंतरिक्ष डोमेन में 100+ स्टार्टअप काम कर रहे हैं

- निवेश- ↑ 3 मिलियन डॉलर (2018) से 65+ मिलियन डॉलर (2021) तक

स्काईरूट एयरोस्पेस अपने विक्रम एस स्पेस लॉन्चर के साथ, अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाली पहली भारतीय प्राइवेट कंपनी बन गई

निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिये पहल

- इन-स्पेस
- न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL)
- इंडियन स्पेस एसोसिएशन (ISpA)

प्रलमिस के लयि:

सीलबंद कवर कार्यवाही, जनहति प्रतरिक्षा दावा कार्यवाही ।

मेन्स के लयि:

सीलबंद कवर कार्यवाही पर सर्वोच्च न्यायालय की टपिपणयिँ

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में [भारत के सर्वोच्च न्यायालय](#) ने न्यायालयों में [सीलबंद कवर कार्यवाही](#) के उपयोग और एक मलयालम चैनल के प्रसारण प्रतर्बिध मामले पर नरिणय सुनाया ।

- न्यायालय ने मीडिया में आवाजों को दबाने एवं [संवैधानिक अधिकारों](#) को कम करने तथा नषिपक्ष सुनवाई की प्रक्रियात्मक गारंटी हेतु सरकार की आलोचना की ।
- न्यायालय ने सीलबंद कवर (मोहरबंद लफाफा) के उपयोग को बदलने हेतु जनहति प्रतरिक्षा दावा कार्यवाही के लयि एक वैकल्पिक प्रक्रिया भी तैयार की ।

सीलबंद कवर कार्यवाही:

- सीलबंद कवर कार्यवाही का उपयोग अक्सर [संवेदनशील या गोपनीय जानकारी](#) जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों या ऐसे मामलों में किया जाता है जहाँ साक्ष्यों के प्रकटीकरण में शामिल व्यक्तियों की गोपनीयता से समझौता हो सकता है ।
- ऐसे मामलों में दस्तावेज़ या साक्ष्य न्यायालय में सीलबंद लफाफे में प्रस्तुत किये जाते हैं और केवल न्यायाधीश एवं एक नामति न्यायिक अधिकारी को सीलबंद लफाफे की सामग्री की जाँच करने की अनुमति होती है ।
 - मामले के पक्षकारों की सीलबंद कवर की सामग्री तक पहुँच नहीं होती है और न्यायालय अपने नरिणयन हेतु केवल सीलबंद कवर में नहिनि जानकारी पर भरोसा करते हैं ।
- सीलबंद कवर कार्यवाही संवेदनशील जानकारी या व्यक्तियों की गोपनीयता की रक्षा करने के साथ [न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता](#) की आवश्यकता को संतुलित करने का एक साधन है ।
 - हालाँकि, सीलबंद कवर के उपयोग ने संवैधानिक अधिकारों एवं कानून के तहत नषिपक्ष सुनवाई की प्रक्रियात्मक गारंटी को कम कर दिया है ।

जनहति प्रतरिक्षा दावा कार्यवाही:

- प्रचिय:
 - सर्वोच्च न्यायालय ने गोपनीयता के लयि राज्य के दावों से नपिटने के दौरान सीलबंद कवर कार्यवाही हेतु "वकिल्प" के रूप में "कम प्रतर्बिधात्मक" जनहति प्रतरिक्षा (PII) दावा कार्यवाही को वकिसति किया ।
 - PII की कार्यवाही एक "गुप्त बैठक" होगी, लेकिन राज्य के PII के दावे को अनुमति देने या खारज़ि करने का एक तर्कपूर्ण आदेश खुले न्यायालय में घोषित करने का प्रावधान है ।
- प्रक्रिया - न्यायमतिर (एमकिस क्यूरी) की भूमिका:
 - न्यायालय द्वारा न्यायमतिर (एमकिस क्यूरी), जिसका अरथ "न्यायालय का मतिर" है, की नयुक्ति की जाएगी, जो जनहति प्रतरिक्षा दावों में शामिल पक्षों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेगा ।
 - न्यायालय द्वारा नयुक्त न्यायमतिर को राज्य द्वारा रोके जाने की माँग की गई है, जिसके लयि उन्हें दस्तावेज़ों को प्रदान किया जाएगा और कार्यवाही से पूर्व आवेदक तथा उनके अधविक्ता के साथ बातचीत करने की अनुमति दी जाएगी ताकि उनके मामले का पता लगाया जा सके ।
 - जनहति प्रतरिक्षा कार्यवाही शुरू होने के पश्चात् न्यायमतिर, आवेदक या उनके अधविक्ता के साथ बातचीत नहीं करेगा जिसके लयि अधविक्ताओं ने दस्तावेज़ को रोके जाने की माँग की है ।
 - न्यायमतिर "अपनी कषमता के अनुसार आवेदक के हतिों का प्रतनिधित्व करेगा" और किसी अन्य व्यक्तिके साथ दस्तावेज़ पर चर्चा नहीं करने की शपथ से बाध्य होगा ।
- तुरुटयिँ/दोष :
 - चूँकि [संवैधानिक अनुच्छेद 145](#) वशिष रूप से अनविर्य करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी नरिणय स्वतंत्र रूप से दिये जाएँ, PII के अनुसार गुप्त बैठक की कार्यवाही इस संवैधानिक आदेश के वरिद्ध हो सकती है ।
 - सर्वोच्च न्यायालय की प्रतक्रिया: जबकि न्यायालय ने यह माना कि जनहति प्रतरिक्षा कार्यवाही एक गुप्त बैठक में होगी, उसने स्पष्ट रूप से कहा कि न्यायालय को स्वतंत्र रूप से नरिणय देने या खारज़ि करने के लयि एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने की आवश्यकता है ।

- इसके अतिरिक्त सीलबंद कवर कार्यवाही न्याय के प्राकृतिक मानदंडों के साथ-साथ पारदर्शी व प्रत्यक्ष न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है तथा PII के दावों का भी न्याय के इन मानकों पर प्रभाव पड़ता है।

सीलबंद कवर कार्यवाही पर सर्वोच्च न्यायालय अन्य टिप्पणियाँ:

- पी. गोपालकृष्णन बनाम केरल राज्य मामला (2019):
 - सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भले ही जाँच जारी हो तथादस्तावेजों से नई जानकारी मलि सकती हो, अभियुक्तों के लिये इसका प्रकटीकरण कानूनी रूप से आवश्यक है।
- INX मीडिया मामला (2019):
 - एक पूर्व केंद्रीय मंत्री को जमानत देने से इंकार करने के दलिली उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन नदिशालय (ED) द्वारा सीलबंद कवर में उपलब्ध कराए गए सबूतों पर आधारित होने के कारण चुनौती दी थी।
 - इस कार्यवाई का आधार नष्टिपक्ष परीक्षण था।
- Cdr अमति कुमार शर्मा बनाम भारत संघ मामला (2022):
 - सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, "प्रभावित पक्ष को प्रासंगिक जानकारी का प्रगटीकरण न करना और नरिणायक प्राधिकरण को सीलबंद कवर में इसका प्रगटीकरण करना एक अनुचित उदाहरण प्रस्तुत करता है।"

स्रोत: द हिंदू

पश्चिमी वकिषोभ से भारत की गेहूँ की फसल को खतरा

प्रलिमिस के लिये:

खाद्य मुद्रास्फीति, गेहूँ, खाद्य फसलें

मेन्स के लिये:

खाद्य उत्पादन में मौसम का प्रभाव, खाद्यान्न सुरक्षा

चर्चा में क्यों?

प्रमुख गेहूँ उत्पादक राज्यों में [पश्चिमी वकिषोभ](#) के प्रभाव के कारण फरवरी माह के दौरान पारा में असामान्य वृद्धि और मार्च के दौरान व्यापक वृष्टि, तेज़ पवनों और ओलावृष्टि सहित हालिया खराब मौसम की स्थिति ने किसानों को उपज, उत्पादन और गेहूँ फसल की गुणवत्ता में संभावित गिरावट के बारे में चिंति कर दिया है।

भारत में गेहूँ की फसल पर असामयिक वृष्टि और पवनों का प्रभाव

- असामयिक वृष्टि और पवनों का प्रभाव:
 - भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि 40-50 किलोमीटर प्रतिघंटे के बीच तूफानी पवनों के साथ वृष्टि, फसल के लिये हानिकारक हो सकती है, खासकर अगर वे पकने और कटाई के चरण के करीब होती हैं। दुर्भाग्य से, फसल के नष्ट होने और खेतों में जलभराव के उदाहरण सामने आए हैं, जो कटाई के लिये तैयार गेहूँ की फसल को अधिक क्षति पहुँचा सकते हैं।
- उत्पादन पर प्रभाव:
 - शोधकर्ताओं के अनुसार, हाल ही में हुई असामयिक वृष्टि से कृषि वर्ष 2022-23 में भारत का गेहूँ उत्पादन 102.9 मीटरकि टन होने की संभावना है, जो केंद्र सरकार के 112 मीटरकि टन के अनुमान से कम है। हालाँकि, केंद्र को यह आशा है कि हाल के प्रतिकूल मौसम की स्थितिके कारण उत्पादन में मामूली कमी के बावजूद इस फसल मौसम में बढ़े हुए रकबे और बेहतर उपज के कारण गेहूँ का उत्पादन 112 मीटरकि टन के करीब रहेगा।
- मूल्य और खाद्यान्न सुरक्षा पर प्रभाव:
 - यदि भारत का गेहूँ उत्पादन अनुमान से कम हो जाता है तो इससे घरेलू बाज़ार में गेहूँ और गेहूँ आधारित उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है।

- इसके अतिरिक्त, गेहूँ के उत्पादन में किसी भी गिरावट से संभावित खাদ्यान सुरक्षा समस्या उत्पन्न हो सकती है।

गेहूँ:

■ परिचय:

- चावल के बाद यह **भारत में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल** है।
- यह देश के उत्तर और उत्तर-पश्चिमी भाग में मुख्य खाद्य फसल है।
- गेहूँ एक **रबी फसल** है जिसे परपिक्व होने के लिये शीत मौसम और तेज़ धूप की आवश्यकता होती है।
- **हरति क्रांति** की सफलता ने रबी फसलों, विशेषकर गेहूँ के विकास में योगदान दिया।

■ तापमान:

- तेज़ धूप के साथ 10-15°C (बुवाई के समय) और 21-26°C (पकने और कटाई के समय) के बीच।

■ आवश्यक वर्षा:

- लगभग 75-100 से.मी.

■ मृदा के प्रकार:

- अच्छी तरह से शुष्क उपजाऊ दोमट और चकिनी दोमट (गंगा-सतलुज मैदान और दक्कन की काली मृदा क्षेत्र)।

■ शीर्ष गेहूँ उत्पादक राज्य:

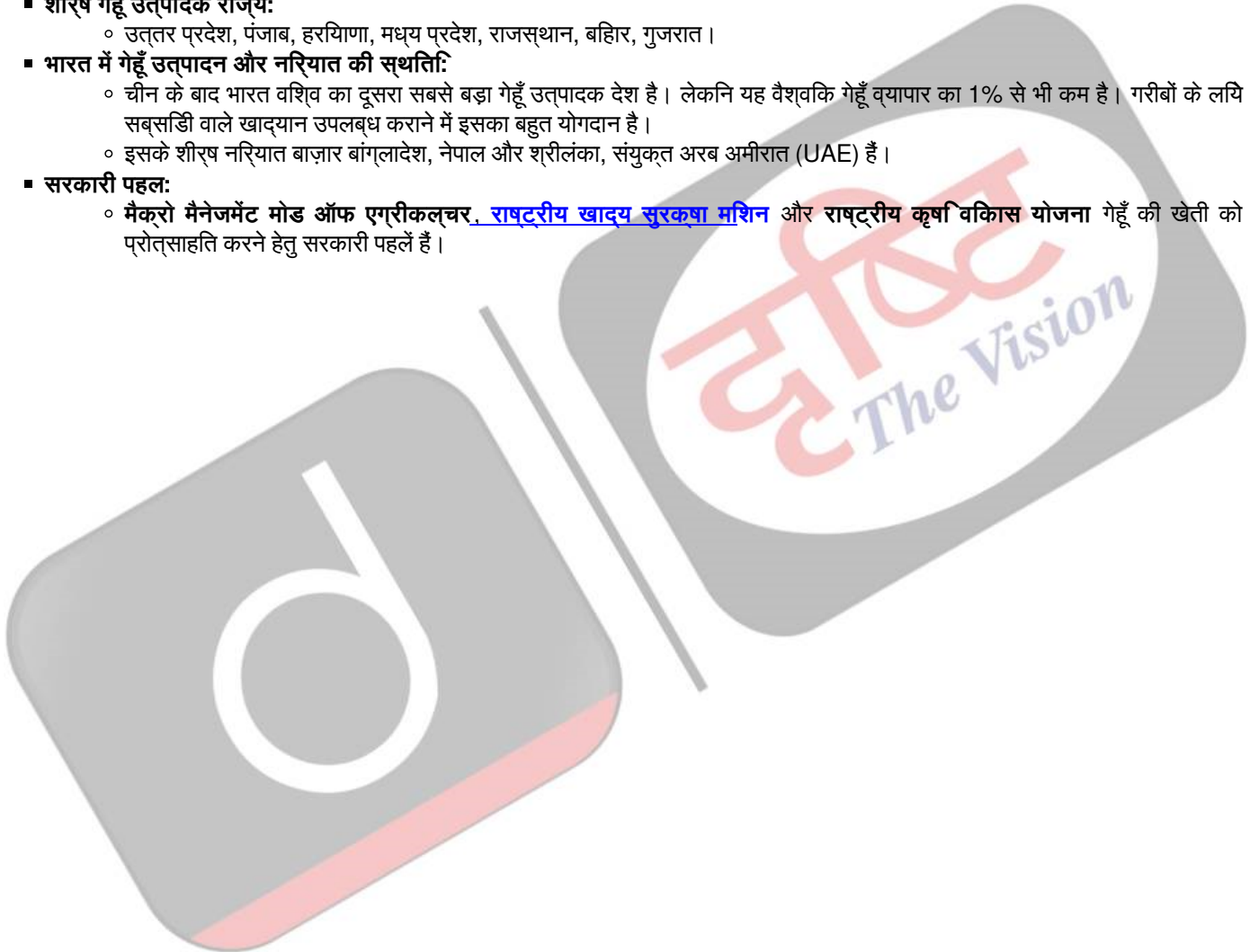
- उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात।

■ भारत में गेहूँ उत्पादन और निर्यात की स्थिति:

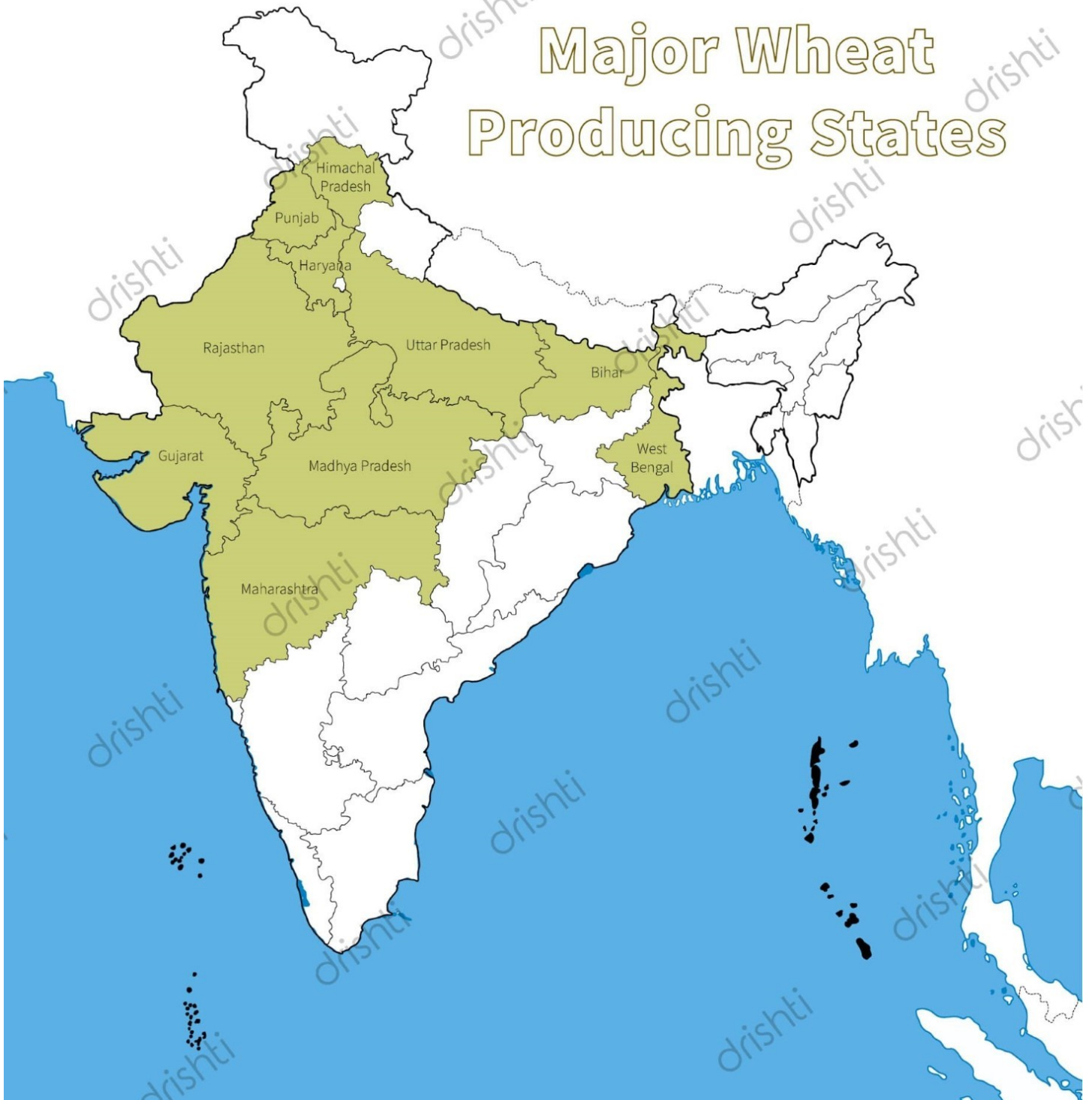
- चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक देश है। लेकिन यह वैश्विक गेहूँ व्यापार का 1% से भी कम है। गरीबों के लिये सब्सिडी वाले खाद्यान उपलब्ध कराने में इसका बहुत योगदान है।
- इसके शीर्ष निर्यात बाज़ार बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) हैं।

■ सरकारी पहल:

- **मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन** और **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** गेहूँ की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु सरकारी पहलें हैं।



Major Wheat Producing States



पश्चिमी वकिषोभः

- [भारत मौसम वजिज्ञान वभिण](#) (India Meteorological Department-IMD) के अनुसार, पश्चिमी वकिषोभ ऐसे तूफान हैं जो कैस्पियन या भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं तथा उत्तर-पश्चिमी भारत में गैर-मानसूनी वर्षा के लिये ज़िम्मेदार होते हैं।
- इन्हें भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले एक 'बहरीष्ण उष्णकटिबंधीय तूफान' के रूप में चिह्नित किया जाता है, जो एक नमिन दबाव का क्षेत्र है तथा उत्तर-पश्चिमी भारत में अचानक वर्षा, हमिपात एवं कोहरे के लिये ज़िम्मेदार हैं।
- पश्चिमी वकिषोभ (Western Disturbances- WD) उत्तरी भारत में वर्षा, हमिपात और कोहरे से संबंधित है। WD भूमध्य सागर और/या अटलांटिक महासागर से नमी प्राप्त करता है।
- WD के कारण शीत ऋतु में मानसून पूर्व वर्षा होती है, जो उत्तरी उपमहाद्वीप में [रबी फसल](#) के विकास के लिये महत्वपूर्ण है।
- WD हमेशा अच्छे मौसम के अग्रदूत नहीं होते हैं। कभी-कभी WDs बाढ़, [फ्लैश फ्लड](#), [भूस्खलन](#), धूल भरी आँधी, ओलावृष्टि और [शीत लहर](#) जैसी चरम मौसमी घटनाओं का कारण बन सकते हैं जो लोगों की जान ले लेते हैं, बुनियादी ढाँचे को नष्ट कर देते हैं और आजीविका को प्रभावित करते हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न . नमिनलखित फसलों पर वचिर कीजिये:

1. कपास
2. मूँगफली
3. चावल
4. गेहूँ

- (a) केवल 1 और 4
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 2 और 3
(d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर : C

स्रोत: द हट्टि

उभरते बाज़ारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के ऋण में बढ़ोत्तरी

प्रलिमिंस के लिये :

संप्रभु ऋण, बाह्य वाणज्यिक ऋण।

मेन्स के लिये :

ऋण संकट में योगदान करने वाले कारक, देशों पर संप्रभु ऋण का प्रभाव।

चर्चा में क्यों?

ग्रीन एंड इनक्लूसिव रकिवरी (DRGR) परियोजना हेतु ऋण राहत रिपोर्ट में कहा गया है कि **उभरते बाज़ारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (EDME) का संप्रभु ऋण वर्ष 2008 से 2021 के बीच 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 178% बढ़कर 3.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो कि [ग्लोबल साउथ](#) में बढ़ते ऋण संकट का संकेत है।**

- ऋण राहत प्रदान करने हेतु बनाए गए [G20](#) के "कॉमन फ्रेमवर्क" में तरुटियाँ पहचानी गई हैं, क्योंकि यह नज़ि और वाणज्यिक लेनदारों सहित सभी लेनदारों को पटल पर लाने तथा ऋण राहत को विकास एवं जलवायु लक्ष्यों से जोड़ने में वफिल रहा है।

नोट: उभरती हुई बाज़ार अर्थव्यवस्था एक विकासशील राष्ट्र की अर्थव्यवस्था है जो वैश्विक बाज़ारों के साथ बढ़ती जा रही है। **उभरती बाज़ार**

अर्थव्यवस्थाओं के रूप में वर्गीकृत देशों में भारत, मैक्सिको, रूस, पाकिस्तान, सऊदी अरब, चीन और ब्राज़ील जैसे विकासिता बाज़ार की कुछ विशेषताएँ (लेकिन सभी नहीं) शामिल हैं।

ऋण संकट के कारक और प्रभाव:

- **EDME नमिन कारणों से कमजोर आर्थिक विकास का अनुभव कर रहे हैं:**
 - [कोविड-19 महामारी](#) से धीमी रकवरी,
 - खाद्यान और ऊर्जा की उच्च कीमतें, और
 - [रूस-युक्रेन संघर्ष](#)
 - बढ़ते जलवायु प्रभाव
 - मज़बूत होता अमेरिकी डॉलर और कई EMDE के मुद्राओं का मूल्यह्रास
- **कमजोर देशों पर प्रभाव:**
 - जलवायु परिवर्तन की चपेट में आने वाले देश सबसे महत्वपूर्ण ऋण संकट का सामना करते हैं।
 - उच्च ऋण सेवा भुगतान से देशों को ऋण चुकाने के लिये अपने वदेशी भंडार के प्रमुख हिस्से को खर्च करना होता है।
 - EDME को तत्काल ऋण राहत प्रदान करने से उनके ऋण भार में कमी होने के साथ इन्हें कम कार्बन उत्सर्जन एवं सामाजिक रूप से समावेशी भवष्य को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

प्रस्तावित समाधान:

- इस रपिर्ट में कॉमन फ्रेमवर्क में सुधार पर बल देने के साथ इस मुद्दे को हल करने हेतु तीन स्तंभों को प्रस्तावित किया गया है।
 - पहले स्तंभ के रूप में **किसी संकटग्रस्त देश को ऋण स्थिरता प्राप्त करने हेतु प्रेरित करने** और विकास तथा जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसकी मदद करने के लिये सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा ऋण में महत्वपूर्ण कटौती किया जाना शामिल है।
 - दूसरे स्तंभ के रूप में **नजि और वाणज्यिक ऋणदाताओं द्वारा** सार्वजनिक ऋणदाताओं की तरह ही ऋण में कटौती किया जाना शामिल है।
 - शेष ऋण के लिये, सरकार को नजि लेनदारों हेतु एक प्रत्याभूत नधिद्वारा समर्थति नए बॉण्ड जारी करने चाहिये।
 - अंतिम स्तंभ उन देशों के लिये है जो ऋण संकट के ज़ोखमि के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ऋण प्रदान कर सकते हैं।
- **ऋण पुनर्संरचना:** रपिर्ट के अनुसार 61 देश जो ऋण संकट के उच्च ज़ोखमि में हैं, उन्हें **812 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है।**
 - इसमें यह भी बताया गया है 55 सबसे अधिक ऋणग्रस्त देशों के लिये अगले पाँच वर्षों में कम से कम **30 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण नलिंबति कर दिया जाना चाहिये।**

G20 कॉमन फ्रेमवर्क:

- **ऋण सेवा नलिंबन पहल (Debt Service Suspension Initiative- DSSI)** से परे ऋण उपचार हेतु **कॉमन फ्रेमवर्क वर्ष 2020 में G20 द्वारा समर्थति एक पहल है**, जिसमें [पेरिस क्लब](#) भी शामिल है, जो संरचनात्मक तरीके से अस्थिर ऋण तथा कम आय वाले देशों का समर्थन करता है।
- फ्रेमवर्क का उद्देश्य कम आय वाले देशों (LIC) की ऋण भेद्यता को दूर करने हेतु एक समन्वित और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करना है, जो कि सबसे गंभीर ऋण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तथा जो **कोविड-19 महामारी** के कारण और अधिक गंभीर हो गई है।

नोट: DRGR प्रोजेक्ट बोस्टन यूनिवर्सिटी ग्लोबल डेवलपमेंट पॉलिसी सेंटर, हेनरकि-बॉल-स्टफिंग और लंदन के SOAS यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस के बीच एक सहयोग है।

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

चीन-ताइवान संघर्ष

प्रलम्बिस के लयि:

चीन-ताइवान संघर्ष, दक्षणि चीन सागर, ताइवान संबंध अधनियिम, वन चाइना पॉलिसी ।

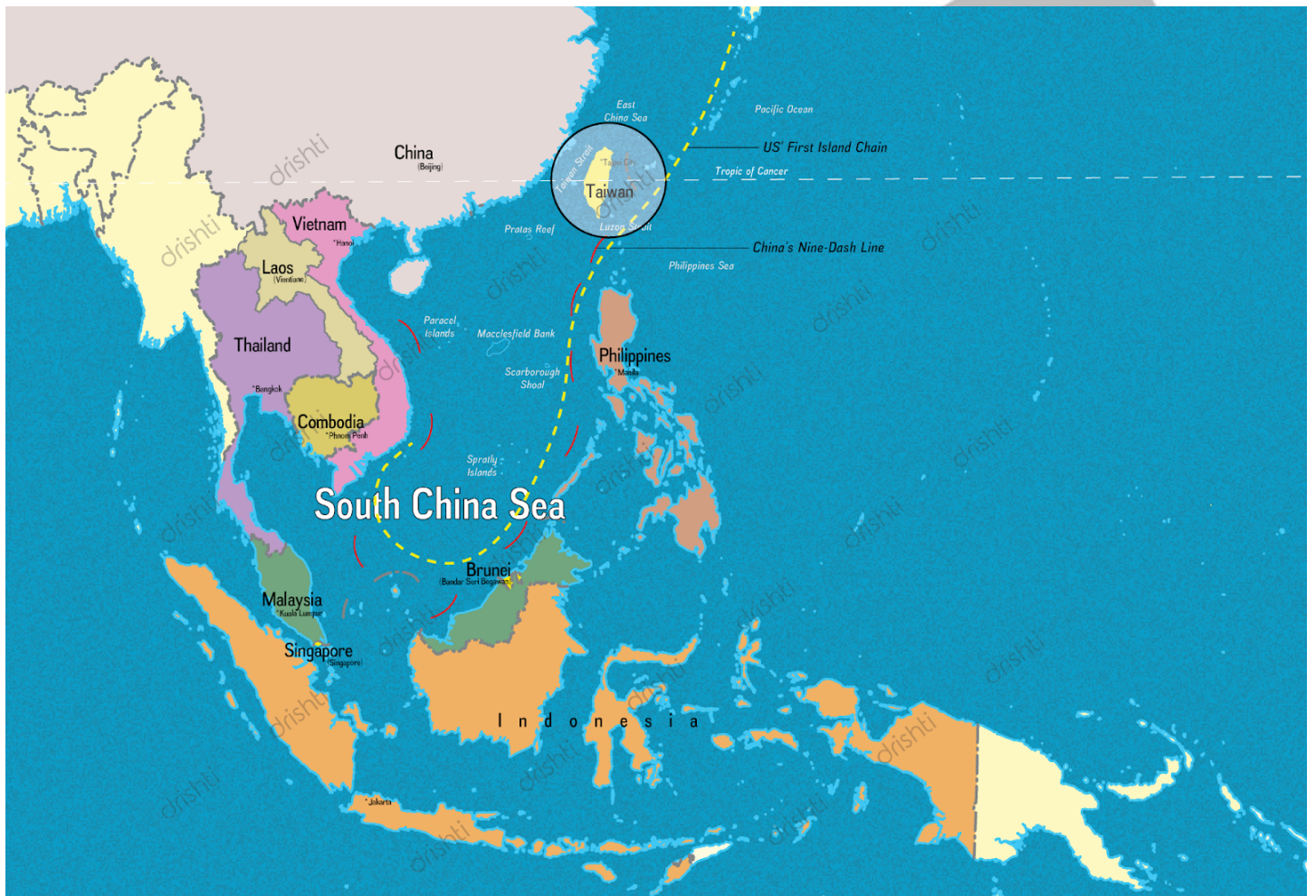
मेन्स के लयि:

ताइवान का महत्त्व, ताइवान मुद्दे पर भारत का रुख, भारत की एक्ट ईस्ट फॉरेन पॉलिसी ।

चर्चा में क्यों?

चीन ने घोषणा की है कविह ताइवान की स्वतंत्रता प्राप्त करने के कसी भी प्रयास या कसी वदिशी हस्तक्षेप के खिलाफ लड़ने के लयि तैयार है ।

- संयुक्त राज्य अमेरिका में ताइवान के राष्ट्रपति की यात्रा के जवाब में चीन ने ताइवान के "सील ऑफ" का अनुकरण करते हुए सैन्य अभ्यास कयि ।
- बड़े पैमाने पर अन्य देशों द्वारा मान्यता प्राप्त ताइवान खुद को एक संप्रभु देश के रूप में देखता है । हालाँकि चीन इसे एक अलग राज्य मानता है और द्वीप को अपने नयितरण में लाने के लयि दृढ़ संकल्पति है ।



वविद का बढि:

- पृष्ठभूमि:
 - चंगि राजवंश (Qing Dynasty) के दौरान ताइवान चीन के नयितरण में आ गया था, लेकिन वर्ष 1895 में चीन-जापान के पहले युद्ध में चीन की हार के बाद इसे जापान को दे दयि गया था ।

- वर्ष 1945 में जापान के **द्वितीय विश्व युद्ध** हारने के बाद चीन ने ताइवान पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन राष्ट्रवादियों और कम्युनिस्टों के बीच गृहयुद्ध के कारण राष्ट्रवादियों को 1949 में ताइवान से पलायन करना पड़ा।
- चियांग काई-शेक के नेतृत्व में कुओमिन्तांग पार्टी ने कई वर्षों तक ताइवान पर शासन किया था और यह यहाँ अभी भी एक प्रमुख राजनीतिक दल है। चीन, ताइवान पर एक चीनी प्रांत के रूप में दावा करता है लेकिन ताइवान का तर्क है कि यह कभी भी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) का हिस्सा नहीं था।
- वर्तमान में चीन के राजनयिक दबाव के कारण केवल 13 देशों ने ही ताइवान को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता दी है।
 - अमेरिका, ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन करता है और ताइपे के साथ संबंध बनाए रखने के साथ उसे हथियार भी बेचता है लेकिन आधिकारिक तौर पर इसने PRC's की "वन चाइना पॉलिसी" का समर्थन किया है।

■ विवाद की पृष्ठभूमि:

- 1950 के दशक में PRC ने ताइवान के नियंत्रण वाले द्वीपों पर बमबारी की, जिससे अमेरिका ने ताइवान के क्षेत्रों की रक्षा के लिये **फॉर्मोसा (ताइवान का पुराना नाम) संकल्प पारित किया था।**
- 1995-96 में चीन द्वारा ताइवान के आसपास के समुद्र में मिसाइलों का परीक्षण किया जाना, **व्यतिनाम युद्ध** के बाद इस क्षेत्र में अमेरिका की सक्रियता का प्रमुख कारण बना था।

■ अद्यतन विकास:

- राष्ट्रपति त्साई के वर्ष 2016 में नरिवाचन के साथ ही ताइवान में स्वतंत्रता के तीव्र समर्थन के चरण की शुरुआत हुई जिस वर्ष 2020 में इनके पुनः नरिवाचन के साथ और भी बल मिला।
- स्वतंत्रता-समर्थक समूहों को चिंता है कि **इनकी आर्थिक निर्भरता इनके लक्ष्यों में बाधा बन सकती है** जबकि ताइवान और साथ ही चीन के कुछ समूहों को उम्मीद है कि लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ने से अंततः स्वतंत्रता-समर्थक समूहों का प्रभाव कमजोर होगा।
- पारस्थितियों में असंतुलन के बावजूद भी ताइवान अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखने में सक्षम रहा है। जैसे-जैसे ताइवान आर्थिक रूप से विकसित होता जा रहा है, ऐसे में **संभव है कि चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ेगा** ही, जिस कारण इस क्षेत्र में परस्थितियों की सूक्ष्म नगरानी करना महत्वपूर्ण हो जाएगा।

ताइवान का सामरिक महत्त्व:

- ताइवान चीन, जापान और फिलीपींस के नजिक **पश्चिमी प्रशांत महासागर** में सामरिक रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। इसका स्थान दक्षिणपूर्व एशिया और **दक्षिण चीन सागर** के लिये एक प्राकृतिक प्रवेश द्वार है जो वैश्विक व्यापार तथा सुरक्षा हेतु आवश्यक है।
- ताइवान **अर्द्धचालक सहित उच्च तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक्स का एक प्रमुख उत्पादक है** और यहाँ विश्व की कुछ सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियाँ भी स्थित हैं।
- ताइवान **विश्व के 60% से अधिक अर्द्धचालक और इसके सबसे उन्नत कस्मि के 90% का उत्पादन करता है।**
- ताइवान के पास एक **अत्याधुनिक और सक्षम सेना है जिसका उद्देश्य अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना है।**
- एशिया-प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे शक्तिसंतुलन को प्रभावित करने की क्षमता के साथ ताइवान क्षेत्रीय और वैश्विक भू-राजनीति का एक प्रमुख केंद्र है।

ताइवान में अमेरिका का नहितार्थ:

- ताइवान का कई द्वीपों पर नियंत्रण है, **जो अमेरिका के लिये अनुकूल क्षेत्र है** और अमेरिका चीन की वस्तुवादी योजनाओं के खिलाफ लाभ उठाने के रूप में इसका उपयोग करना चाहता है।
- अमेरिका का ताइवान के साथ आधिकारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं, लेकिन द्वीप की रक्षा करने के साधन प्रदान करने हेतु **अमेरिकी कानून (ताइवान संबंध अधिनियम, 1979)** से बाध्य है।
- यह ताइवान के लिये अब तक की सबसे बड़ी हथियार डील है तथा एक **'सामरिक अस्पष्टता' नीति** का पालन करता है।

ताइवान मुद्दे पर भारत का रुख:

■ भारत-ताइवान संबंध:

- **भारत की 'एकट ईसट' विदेश नीति** के एक अंग के रूप में भारत ने ताइवान के साथ व्यापार और निवेश के साथ-साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय मुद्दों और लोगों के पारस्परिक संपर्क के क्षेत्र में गहन सहयोग विकसित करने का प्रयास किया है।
- औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं होने के बावजूद भारत एवं ताइवान **नवंबर 1995 से एक दूसरे की राजधानियों में प्रतिनिधिक कार्यालय बनाए हुए हैं जो वास्तविक दूतावासों के रूप में कार्य करते हैं।** इन कार्यालयों ने उच्चस्तरीय यात्राओं की सुविधा प्रदान की है तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने में मदद की है।

■ वन चाइना पॉलिसी:

- भारत वन चाइना पॉलिसी का पालन करता है जो ताइवान को चीन के हिस्से के रूप में मान्यता देता है।
- हालाँकि भारत को यह भी उम्मीद है कि **चीन जम्मू और कश्मीर जैसे क्षेत्रों पर भारत की संप्रभुता को मान्यता देगा।**
- भारत ने हाल ही में वन चाइना पॉलिसी के पालन का जिक्र करना बंद कर दिया है। यद्यपि ताइवान के साथ भारत के संबंध चीन के साथ अपने संबंधों के कारण प्रतर्बिधित हैं, वह ताइवान को एक महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार तथा सामरिक सहयोगी के रूप में देखता है।
- **ताइवान के साथ भारत के बढ़ते संबंधों को क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के कदम के रूप में देखा जा रहा है।**

आगे की राह

- रूस की अर्थव्यवस्था की तुलना में, **चीनी अर्थव्यवस्था** विश्व अर्थव्यवस्था में कहीं अधिक एकीकृत है। इसलिये, यदि चीन ताइवान पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है, तो विशेष रूप से नकिटतम यूक्रेन संकट को ध्यान में रखते हुए चीन बहुत सावधान रहेगा।
- चाहे कुछ भी हो, ताइवान पर चीन के आक्रमण के पश्चात एशिया की अलग तरीके से पहचान होगी, इसलिये ताइवान का मुद्दा सरिफ नैतिकता से अधिक और एक सफल लोकतंत्र का वनिश करने के बारे में है।
- इसके अतिरिक्त, जसि तरह चीन अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना **चीन-पाकस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)** के माध्यम से पाकस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है, उसी तरह भारत वन चाइना पॉलिसी पर पुनर्विचार कर सकता है और ताइवान के साथ अपने संबंधों को चीन की मुख्य भूमि से अलग मान सकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. "चीन अपने आर्थिक संबंधों और सकारात्मक व्यापार अधिशेष को एशिया में संभाव्य सैनिकी शक्ति हैसियत को वकिसति करने के लिये उपकरणों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है"। इस कथन के प्रकाश में उसके पड़ोसी के रूप में भारत पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिये। (2017)

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/12-04-2023/print>

